17 दिसंबर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल-जीवन-हरियाली यात्रा का तीसरा चरण कैमूर से शुरू होगा। 18 दिसंबर को गया के पहाड़पुर में राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान में कैबिनेट की बैठक होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 दिसंबर 2019

लोकतंत्र की मशाल आज मेहनतकशों के हाथ

आरपीएन मिश्र, रांची

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

▸ **खनिज, उद्योग, पर्यटन और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हैं चौथे चरण की 15 सीटें**

विकास में जनभागीदारी का लक्ष्य लेकर निकली चुनावी मशाल झारखंड के 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए अब चौथे चरण के उन 15 इलाकों में जा पहुंची है जो खनिज, उद्योग और वन संपदा के बल पर राज्य की अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत की खूबियों से इसका गौरव भी बढ़ाते हैं। विकास की इस मशाल को राज्यभर की 81 विधानसभा सीटों की परिक्रमा करते हुए विधानसभा के द्वार तक पहुंचना है। फिलहाल मशाल थामे धनबाद, झरिया, सिंदरी, बाघमारा, टुंडी, निरसा, बोकारो, चंदनकियारी, गिरिडीह, जमुआ, गांडेय, डुमरी, बगोदर, देवघर और मधुपुर की जिम्मेदारी है कि वे मशाल की ज्योति को अपने बुलंद इरादों की अग्नि से इतनी प्रज्ज्वलित और प्रखर कर दें कि अगले चरण के चुनाव वाले इलाकों के लोग भी इसे संदेश, सबक और चुनौती के रूप में लें। अपने खनिजों और उद्योगों से राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हाथ में आज एक बार फिर मतदान के अमोघ अस्त्र से नया झारखंड गढ़कर अपने सपनों का राज्य बनाने का अवसर आया है। अच्छी बात ये है कि इन इलाकों के लोगों ने पिछले चुनावों में जागरूकता का परिचय देते हुए मतदान का आंकड़ा 65-70 फीसद तक और कहीं कहीं तो उसके भी पार पहुंचा दिया था।

अपने अथाह भंडार से रोज हजारों टन कोयला उगलने वाले धनबाद, झरिया, निरसा, टुंडी, बोकारो, गिरिडीह समेत इन तमाम इलाकों की इस समृद्ध पहचान के साथ झारखंड के अन्य हिस्सों की तरह गरीबी, बेकारी और बदहाली भी साथ-साथ चलती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, पत्थर और अन्य खनिज स्थानीय लोगों की समृद्धि का आधार नहीं बन सके हैं। दीपक तले अंधेरा वाली कहावत की तरह। फिर भी मेहनत और संघर्ष के बल पर मंजिल हासिल करने का जज्बा, सीमित आवश्यकताएं, कभी भी हार न मानने की जीवटता, गिर-गिर कर संभलने का जज्बा और विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त व ऊर्जावान बने रहने की खासियत यहां के लोगों को बाकियों से अलग करती है। जरूरत इस ताकत और क्षमता को सही दिशा देने की है। लोकतंत्र के महापर्व पर सोमवार को हमें अपनी इस ऊर्जा को मतदान की ताकत में बदलना है।

समृद्धि के द्वारों से लेकर आस्था और संस्कृति के सेतु तक : क्षमताओं की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में फैले कोयला उद्योग के अलावा स्टील सिटी के रूप में विख्यात बोकारो और खाद कारखाने के लिए मशहूर सिंदरी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गौरव के चिह्नों की भी कमी नहीं। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का वैद्यनाथ धाम जहां देश-दुनिया में भक्ति और अध्यात्म की धारा बहा रहा है, वहीं गिरिडीह में स्थित जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ से सत्य और अहिंसा का संदेश दुनियाभर में फैल रहा है। धनबाद, चंदनकियारी और निरसा के इलाके बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण अभी भी दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए धनबाद में चुनाव सामग्री ले जाते मतदानकर्मी। प्रेट्र

221 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे 47.85 लाख मतदाता

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चौथे चरण का मतदान होगा। इसमें कोयलांचल की 13 व संताल की दो सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्वच्छ व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण के चुनाव में दो मंत्री, सात पूर्व मंत्री तथा 14 वर्तमान विधायकों का भाग्य तय होगा। कुल 47,85,009 मतदाता 221 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। कुल प्रत्याशियों में 198 पुरुष तथा 22 महिला हैं। पहली बार एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 6,101 मतदान केंद्रों में 4,203 संवेदनशील तथा अति संवेदनशील हैं। 1,898 मतदान केंद्र ही सामान्य हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा में 50 सीटों पर चुनाव हो चुका है। चौथे चरण के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 1,216 दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान अपने घर पर ही किया। बोकारो में 351, धनबाद में 767 तथा देवघर में 98 ने इस सुविधा का लाभ उठाया। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 1,367 ऐसे मतदाताओं ने इच्छा जाहिर कर फार्म भरे थे, जिनमें 30 को छोड़कर सभी के फार्म सही पाए गए। चुनाव आयोग द्वारा गठित टीम ने 1,216 मतदाताओं के घरों में जाकर मतदान कराया। इससे पहले उन्हें वीडियो दिखाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बाकी मतदाता अपने घरों में नहीं पाए गए। बता दें कि भारत में पहली बार झारखंड से यह व्यवस्था शुरू की गई है।

स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई में शामिल होगा नदी संरक्षण

फैसला ▸ कानपुर में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बनी सहमति

प्राथमिकता के आधार पर मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य शैक्षिक संस्थानों में करेंगे लागू

बृजेश दुबे, कानपुर

स्कूल-कॉलेज में जल्द ही नदी संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य प्राथमिकता के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार कराकर इसे विश्वविद्यालय और स्कूलों में लागू कराएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल इस एजेंडे पर सहमति बन गई है।

नमामि गंगे से अर्थ गंगा की ओर बढ़ रहे गंगा सफाई अभियान में जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर है। शनिवार को कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तय समय से डेढ़ घंटे तक अधिक चली परिषद बैठक में यह दिखा भी। 14 प्रमुख एजेंडे में जन भागीदारी, आय, पर्यटन और शिक्षा भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बिंदु प्रमुखता से सामने आया कि अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने की बेहद जरूरत है, जो शिक्षा एवं शैक्षिक गतिविधियों से संभव है।

इसके पीछे की मंशा साफ है। चूंकि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों में नदियों के प्रदूषण को लेकर शोध होते रहते हैं, सो इस दिशा में तो काम हुआ लेकिन नदी व पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही बंधे होने के कारण आमजन का विषय नहीं बन पाए।

बैठक में जोर दिया गया कि नदी संरक्षण से आमजन को जोड़ना बहुत जरूरी है। इस पर स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक, नदी संरक्षण को पाठ्यक्रम के प्रमुख हिस्से के रूप में शामिल करने पर सब सहमत हुए। हालांकि राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यकारिणी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है और शनिवार की बैठक में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था फिर भी माना जा रहा है कि गंगा केंद्रित सोच के साथ हुई परिषद की बैठक में हुआ निर्णय सभी लागू करेंगे। एक उच्चपदस्थ सूत्र के अनुसार, इस एजेंडे पर मानव संसाधन मंत्रालय से पहले ही चर्चा हो चुकी है, उनकी सैद्धांतिक सहमति भी है, इसलिए इस प्रस्ताव पर लागू करने के मोड में ही चर्चा हुई, जिसे सभी ने माना।

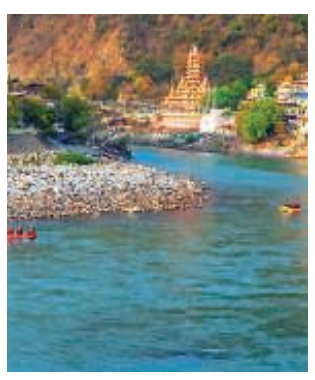

प्रतीकात्मक

सूचना, शिक्षा और संचार से करेंगे जागरूक

पाठ्यक्रम में नदी संरक्षण को शामिल करने के अलावा स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के आइईसी (इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन यानी सूचना, शिक्षा और संचार) मोड का सहारा लिया जाएगा। इसके तह सूचना इकट्ठा कर शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा पाने वाले लोगों में व्यावहारिक परिवर्तन के लिए उसका प्रचार करेंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होने पर छात्र नदी संरक्षण के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से जागरूक कर पाएंगे।

छात्रों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ेगा विवि अनुदान आयोग

नईदुनिया, भोपाल

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को अब सामाजिक सरोकार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाएगी। अब तक अभियान में सिर्फ तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अच्छा प्रतिसाद मिलने पर अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ने की तैयारी है।

उन्नत भारत के तहत शुरू की गई इस योजना में यूजीसी ने सामाजिक सरोकारों को लेकर पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस पूरी कवायद के पीछे यूजीसी का मकसद है कि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में न सिर्फ जानकारी मिल सके, बल्कि उसका समाधान भी किया जा सके। साथ ही केंद्र सरकार की नए भारत निर्माण की योजना को साकार किया जा सके। यही वजह है कि यूजीसी ने इस अभियान को पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित रखा है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर अपने संस्थानों से दो शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। इन सभी का प्रशिक्षण कुछ दिन में शुरू होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा। इसके साथ ही संस्थानों से इसे लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने आसपास के पांच गांवों को गोद लेना होगा। जहां वह छात्रों की मदद से उन्हें सरकार से जुड़ी योजनाओं और डिजिटल पेमेंट आदि की जानकारी देंगे। साथ ही उनके रहन-सहन और स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। फैकल्टी और छात्र महिलाओं और बच्चों को आ रही परेशानियों के बारे में भी जानेंगे। इस बारे में ये लोग अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय यूजीसी के जरिये केंद्र सरकार तक भेजेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रो. डीपी सिंह का कहना है कि सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फाइल

पंजाब भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में दिखेगी 2022 की झलक

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

▸ **नए साल में राज्य में भाजपा को मिलेगा नया प्रधान**

▸ **जिला प्रधान चुनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा चुनाव**

पंजाब में संगठन चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव की कमान किसके हाथों में होगी, इसका पता नए साल में ही चल पाएगा। नए प्रदेश प्रधान के चयन के साथ ही भाजपा का अगले विधानसभा चुनाव को लेकर रुख स्पष्ट हो जाएगा। जिला प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया में देरी के कारण प्रदेश प्रधान के चुनाव में देरी हो गई है। पहले जिला प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी थी। अब यह 25 दिसंबर तक पूरी होगी। इसके बाद ही प्रदेश प्रधान का चुनाव होगा।

गठबंधन निभाना बड़ी चुनौती : भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि वह अकाली दल के साथ गठबंधन को भी निभाना चाहती है। साथ ही भाजपा में उठ रही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग को भी पूरा करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत और राज्य में अकाली दल के गिरते ग्राफ के बाद से ही भाजपा में यह मांग उठती रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में 23 से ज्यादा सीटें दी जाएं।

नए-पुराने चेहरों के बीच द्वंद्व : 2022 के लिए भाजपा में इन दिनों नए और पुराने चेहरों के बीच में द्वंद्व चल रहा है।

नए चेहरे : पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, पार्टी के महासचिव राकेश राठौर, प्रवीण बांसल, उप प्रधान जीवन गुप्ता, नरेंद्र परमार।

पुराने चेहरे : मौजूदा प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक, मनोरंजन कालिया, अश्विनी शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ।

दोबारा दावा ठोक रहे मलिक : श्वेत मलिक दोबारा एक पारी खेलने के लिए दावा ठोंक रहे हैं, जबकि मनोरंजन कालिया और अश्विनी शर्मा पहले भी पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अकाली दल-भाजपा की सरकार में अनिल जोशी ऐसे मंत्री रहे, जिन्होंने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक अकाली दल के साथ दो-दो हाथ किए। सदन में 'मैं आतंकवादी हूं' कहने पर जोशी ने अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा को आड़े हाथ लिया था। अपने छोटे भाई पर गोली चलने के बाद जोशी अकाली दल के खिलाफ डट कर खड़े हुए थे। तीक्ष्ण सूद सरकार और संगठन के कामकाज में संतुलन बनाने वाले नेता हैं। राकेश राठौर, जीवन गुप्ता, प्रवीण बांसल और तरुण चुघ को संगठन के कामकाज की अच्छी समझ है।

आगरा बैठक में कृष्णा सर्किट के विस्तार का बुना जाएगा ताना-बाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाणा व उत्तर प्रदेश सीमा पर जमीन और आगरा नहर के सिंचाई पानी संबंधी विवादित मुद्दों पर चर्चा के बाद अब इस माह के अंत में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आगरा में कृष्णा सर्किट के विस्तार का ताना-बाना बुनेंगे। इसके लिए शनिवार को लखनऊ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।

कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट विकास योजना के प्रथम चरण के तहत केंद्र सरकार से अब तक हरियाणा को 95 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। अब इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र को मथुरा-वृंदावन से जोड़ने की योजना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोनों राज्यों ने अनेक विवादित मुद्दे खत्म करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर जहां पहले ही लखवाड़, रेणूका और किशाऊ बांध परियोजना पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री समझौता कर चुके हैं। तीनों बांध परियोजनाओं से हरियाणा को सबसे ज्यादा 47.82 फीसद पानी मिलेगा। इसके अलावा दो फरवरी, 2018 को दोनों राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार करने के लिए भी समझौता हो चुका है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन व्यवस्था की खामियां दूर करने के लिए 35 वर्ष बाद समझौता हुआ था। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश ने फरीदाबाद के सूरजकंड में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भी थीम स्टेट के रूप में भागीदारी की थी।

राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में भी कृष्णा सर्किट के विकास में तेजी लाने सहित विस्तार की बाबत विषय शामिल किया था। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत और पानीपत जिलों के ऐतिहासिक स्थल इस कृष्णा सर्किट में शामिल होंगे। राज्य में सिंघु घाटी सभ्यता के अहम स्थलों को विकसित करने के लिए हड़प्पा सर्किट विकसित करने पर भी काम किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों पर पर्यटन से लेकर फार्म हाउस पर्यटन पर भी जोर दिया जाएगा।

मनोहर लाल फाइल

योगी आदित्यनाथ फाइल

मप्र में किसानों को अब एक लाख रुपये तक कर्जमाफी

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार जय किसान ऋण मुक्ति योजना के दूसरे चरण में 50 हजार से एक लाख रुपये तक किसानों की कर्जमाफी करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर करेंगे। इससे लगभग पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, अब करीब 12 लाख किसान कर्जमाफी के लिए बचे हैं। इनमें पांच लाख किसान ऐसे हैं, जिन पर चालू खाते में 50 हजार से एक लाख रुपये का कर्ज है। झाबुआ और आलीराजपुर में यह दौर पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में 17 दिसंबर से कर्जमाफी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलेवार लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची बैंकों को दे दी गई है। जिलों से बैंकों को अब यह आदेश जारी होंगे। प्रदेश में अभी तक 20 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार कर्जमाफी दे चुकी है। इसमें दो लाख रुपये तक एनपीए लोन माफ करने के साथ चालू खाते पर 50 हजार रुपये तक कर्जमाफी दी गई है। इसमें किसानों को सात हजार 154 करोड़ से ज्यादा की कर्जमाफी मिली है।

उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की तैयारी

केदार दत्त, देहरादून

▸ **बड़ा कदम-गांवों से पलायन थामने को चल रही कवायद के दौरान आया सुझाव**

▸ **बीते 19 वर्षों में 1702 गांव हो चुके हैं निर्जन**

गांवों से निरंतर हो रहे पलायन को थामने की कवायद में जुटी उत्तराखंड सरकार अब एक अहम कदम उठाने जा रही है। पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर पर परीक्षण के बाद नए साल में ये व्यवस्था अमल में आएगी। इससे पलायन रोकने को चलने वाली तमाम योजनाओं के लिए विभागवार धन मुहैया कराया जाएगा, ताकि कार्य तेजी से हो सकें।

उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। खासकर, पर्वतीय क्षेत्र के गांव पलायन से निरंतर खाली हो रहे हैं। बीते 19 वर्षों में 1702 गांव निर्जन होना इसकी तस्दीक करता है। सैकड़ों गांवों में जनसंख्या अंगुलियों में गिनने लायक रह गई है। इसे देखते हुए पलायन आयोग ने अगले पांच साल गांवों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। हालांकि, पलायन रोकने को सरकार कवायद में जुटी है। प्रभावित गांवों के लिए अब विभागवार कार्ययोजनाएं तैयार हो रही हैं। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। नीति आयोग ने भी पलायन रोकने के उपायों को लेकर विशेष रुचि ली है। इस बीच हाल में मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने पलायन रोकने को अलग से बजट की व्यवस्था का सुझाव रखा। बजट प्रविधान होने से पलायन रोकने को चलने वाली गतिविधियों को धन की दिक्कत नहीं रहेगी। उधर, इसे लेकर शासन स्तर पर गहनता से मंथन चल रहा है। उम्मीद है नए साल में ये व्यवस्था अमल में आ जाएगी।

> पलायन को गंभीरता से लिया गया है। पलायन रोकने को अलग से बजट की व्यवस्था के मद्देनजर ग्राम्य विकास विभाग इसका प्रस्ताव देगा। परीक्षण के बाद इस व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा।
>
> -अमित नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखंड

झारखंड में राहुल गांधी की चुनावी सभाओं पर लग सकती है रोक

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभाओं पर रोक लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के गोड्डा और साहिबगंज की जनसभाओं में 12 दिसंबर को दिए गए वक्तव्य पर चुनाव आयोग ने ब्योरा तलब किया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने साहिबगंज और गोड्डा के उपायुक्त से राहुल गांधी के भाषण के अंश को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल के गोड्डा में दिए भाषण को आधार बना शिकायत की थी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर राहुल गांधी की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि 12 दिसंबर को गोड्डा की सभा में राहुल गांधी ने अपमानजनक और शर्मसार करने वाला बयान दिया था। कहा था कि आज भारत मेक इन इंडिया के बजाय रेप इन इंडिया बन गया है। राहुल के इस बयान को लेकर संसद में भी काफी हंगामा हुआ था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी झारखंड में अब तक पांच सभाएं कर चुके हैं।

तलाश जारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नाम चर्चा में, सभी गुटों की तरफ से अपने नेताओं के नाम किए जा रहे आगे

मप्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला नए साल में ही संभव

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब नए साल में ही नया अध्यक्ष मिल पाएगा। प्रदेश में सरकार बने एक साल हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए हाईकमान गंभीर है। नए अध्यक्ष को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कमलनाथ सरकार के सदस्यों सहित कुछ हारे हुए पूर्व मंत्रियों के नामों की चर्चा है।

विधानसभा चुनाव के छह महीने पहले कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ संगठन की जवाबदारी से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन विधानसभा में संतुलन बनाए रखने के लिए संगठन की कमान किसी और को सौंपकर नया शक्ति केंद्र बनाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा आलाकमान ने कमलनाथ को ही सत्ता के साथ-साथ संगठन की जवाबदारी सौंपे रखी।

विधानसभा में कमलनाथ सरकार के आरामदायक स्थिति में आने के बाद अब हाईकमान पर संगठन का नया मुखिया बनाने के लिए सभी गुटों का दबाव है। दिल्ली में भारत बचाओ रैली के बाद प्रदेश के अधिकांश नेताओं ने हाईकमान के सामने जल्द से जल्द नए अध्यक्ष पर फैसले की बात भी रखी है।

इन नामों की चर्चा : नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधायक कांतिलाल भूरिया व बिसाहूलाल सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, गृह मंत्री बाला बच्चन व वन मंत्री उमंग सिंघार के नाम शामिल हैं। सिंधिया के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव में हार के बाद भी उनके क्षेत्र व मालवा में सक्रियता के कारण प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम गाहे-बगाहे चर्चा में आता रहा है। उनके समर्थक मंत्री, विधायक, पदाधिकारी भी लगातार उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग उठाते रहे हैं। हालांकि उनके खेमे से पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का नाम भी चर्चा में आया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खेमे की तरफ से विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले कांतिलाल भूरिया को एक बार और यह जिम्मेदार देने को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के विश्वस्त बाला बच्चन भी इस दौड़ में लगातार बने हुए हैं और उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री समर्थक करते रहे हैं। इधर, विधानसभा व लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए एक साल में अप्रत्यक्ष तौर पर कई बार शक्ति प्रदर्शन हो चुके हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइल

सरकार-संगठन में सामंजस्य की जद्दोजहद

सूत्रों के मुताबिक, अधिकांश नेताओं की यह कोशिश है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करे। इससे जहां संगठन का काम सुगमता से चल सकेगा, वहीं सत्ता को भी मुश्किलें कम आएंगी। हालांकि, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सरकार के सही-गलत फैसलों पर सही राय रखने वाले व्यक्ति को नया प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, जिससे संगठन को मजबूती मिले और सरकार भी सही दिशा में चल सके।

नीति और बुनियादी ढांचे की तैयारी में शीर्ष पर छत्तीसगढ़

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ नीति और बुनियादी ढांचा तैयार करने और मिशन मोड वाली परियोजनाओं के प्रदर्शन में देश में शीर्ष पर रहा है। गुरुग्राम की एक निजी सर्वे एजेंसी ने रविवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। भारत के डिजिटल राज्य रिपोर्ट 2019 नाम से जारी इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश पांचवें स्थान पर है। वहीं, महाराष्ट्र दूसरे, हरियाणा तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है।

रिपोर्ट जारी करते हुए सर्वे एजेंसी कोएस एज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल देव सिंह ने कहा देशभर में डिजिटल इंडिया रफ्तार पकड़ रहा है। पहले यह केवल कुछ बड़े राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के राज्यों तक सीमित था। अब इसमें उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हो रहे हैं।

यह रिपोर्ट राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दो व्यापक मानकों नीति और बुनियादी ढांचे की तैयारी (पीआइआर) व मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के प्रदर्शन के आकलन के आधार पर तैयार की गई है। इस आकलन में पीआइआर और एमएमपी के 128 मानकों को शामिल किया गया है।

हरियाणा की ऊंची छलांग

मध्य प्रदेश 2017 में इस सूची में शीर्ष पर था। इस साल के अध्ययन में वह फिसलकर पांचवें स्थान पर आ गया है। सबसे ऊंची छलांग हरियाण ने लगाई है जो 2017 में दसवें स्थान पर था और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। जो अन्य राज्य और संघ शासित प्रदेश लंबी छलांग लगाने में सफल रहे हैं उनमें गोवा, बिहार, चंडीगढ़ और असम शामिल हैं।